Shri Sangamna: May I know whether Orissa by itself is short of engineers and if so how is the problem of executing the river valley projects and other industrial schemes in Orissa faced?

Shri S. N. Mishra: In framing their proposals for the Second Five Year Plan, the Government of Orissa must have taken all these into account.

Shri Sanganna: May I know whether the Government of Orissa have submitted their proposal for inclusion in the First Five Year Plan of the State?

Shri S. N. Mishra: I think the hon. Member refers to the Second Five Year Plan. We have been told by that Government that in their plan for education this scheme has already been included.

N.E.S Training Centre at Hyderabad *1450. Shri Janardhan Reddy: Will the Minister of Planning be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that one more centre has been opened in Hyderabad State to train the personnels of the National Extension Service Blocks;
- (b) if so, how many persons are undergoing training in that centre; and
- (c) the number of those who have been trained so far ?

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra): (a) to (c). The hon. Member is perhaps referring to the proposal to set up a Centre at Hyderabad for the training of Block Level Extension Officers in Co-operation. The matter is under consideration of the Ministry of Food and Agriculture.

श्री जनार्बन रेड्डी: माननीय मंत्री ने २४ सितम्बर मेरे सवाल ७२२८ का जवाब दते हुये फरमाया था कि वहां पर एक धौर सेंटर खोला जायगा। तो जब सेंटर खोला जायेगा तो जो ब्लाक्स पहले दिये गये थे उससे धव की मर्तबा दुगने होंगे?

श्री एस॰ एन॰ मिश्रः मैंने प्रपने जवाब में बताया है कि यह ट्रेनिंग सेंटर ब्लाक लेवल एक्सटेंशन ग्राफिसर्स इन को ग्रापरेशन के लिये होगा, सहकारिता के काम के लिये। भीर चार केंद्र वहां पहले से काम करते हैं, लेकिन खासकर सहकारिता के काम के लिये हैं।

भी हेडा: साहकार के लिये?

भी एम० एम० मिश्र : यह ट्रेनिंग सेंटर जो ब्लाक लेवल एक्सटेंशन भाफिसर्स हैं सासकर उनके लिये है भीर उसके बारे में फूड एंड एग्रिकल्वर मिनिस्ट्री गीर कर रही है।

Shri Heda: In view of the fact that the Hyderabad Government is feeling the paucity of the village level workers and therefore, is not able to take up the quota of NES blocks, will the second centre for training of the NES personnel be opened soon?

Shri S. N. Mishra: The presumption that we are not able take up the NES blocks because of the paucity of village level workers and all that is not correct because we have not so far been held up on that account.

भी जनार्वन रेड्डी: यह ब्लाक्स जो स्टेट्स को दिये जाते हैं वह बराबर तक-सीम होते हैं या नहीं, इस को देखने के लिये माननीय मंत्री क्या कोई निगरानी रखते हैं, जैसे हैदराबाद गवर्न मेन्ट मनमानी तौर पर उन को तकसीम कर रही है?

भी एस० एन० सिभाः प्रगर माननीय सदस्य का यह विचार है कि जो बटवारा होता है विस्तार खण्ड योजनामों के बारे में वह योजनामों का वह न्यायपूर्ण ढंग से होता है या नहीं, तो इसके सम्बन्ध में निगरानी क लिये ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, वह तो विचार विमर्श करके प्रापस में कि किस तरह से राज्य सरकार प्रपनी योजनामों को चालू कर सकती है भीर क्या करना चाहिये, इन सब बातों के भाभार पर होता है, इसके लिये कोई न्यायालय नहीं है।

श्री जनार्वन रेड्डी: क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि जिस वक्त स्टेट गवनैमेंट इन ब्लाक्स को स्टेट में तकसीम करती है, उस वक्त पार्लियामेंट के मेम्बरों से कोई मश्विरा नहीं लिया जाता है, जैसे कि हैदरा-बाद गवनैमेंट ने किया है, इसके लिये यहां की गवनैमेंट क्या तजवीज कर रही है ?

बी एस॰ एन॰ जिथा: पालियामेंट के मेम्बरान या दूसरे जो भाई हैं उनका सहयोग तो प्रोजेक्ट ऐडवाइचरी कमेटी में लिया जाता है जिसमें प्रोजेक्ट इव होती है। यह बटवारा किस कदर हो, इसमें भी पार्लियामेंट के मेम्बरों की राय स्री जाय, यह तो एक नया मुझाव है।

डा॰ सुरज्ञ चन्द्र : यह जो केन्द्र, धापने कहा कि खोलने वाले हैं, वह धौरंगाबाद में खोलने का विचार है ?

भी एस॰ एन॰ मिर्भः मैं उसके स्थान का निर्देश नहीं कर सकता।

Shri R. S. Diwan: Rs. 30 lakhs were granted by the Central Government to the Hyderabad Government to be spent on building but this amount has not been spent during the last three years for want of technical personnel. May I know whether the officers trained in these centres will be useful for bunding work also?

Shri S. N. Mishra: As I have already indicated, this relates to co-operation.

Welfare of the Tribals

*1451. Shri Deogam: Will the Minister of Planning be pleased to state whether any special schemes for giving the Tribal people all possible support for the development of education with a view to bringing them educationally at par with more advanced people of the State, have been formulated by the Bihar Government for inclusion in the Second Five Year Plan?

The Deputy Minister of Planning: (Shri S. N. Mishra): Yes, Sir.

भी बबगम : क्या यह सत्य है कि पिछले बो वर्षों में के दुर्भिक्ष के कारण वहां के लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं भौर बच्चों को भ्रपनी पढ़ाई जारी रखने में भी बहुत मुश्किल हो रही है?

भी एस॰ एन॰ सिम्ब : जी हां, बिहार के उस हिस्से में सूखे के कारण बहुत परे-धानियां हैं भौर यह जाहिर है कि उनकी बजह से वहां के बच्चों की शिक्षा पर भी भसर होता होगा ।

श्री यथगमः : क्या उस इलाके में जहां दुर्भिक्ष पड़ा हुन्ना है कोई विशेष सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ?

श्री एस॰ एन॰ मिश्र : राज्य सरकार तात्कालिक सहायता क्या देना चाहती है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। हमारा विचार है कि जरूर कुछ ऐसे उपाय किये गये होंगे जिन से कि इन लोगों की मदद हो। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन लोगों की शिक्षा दीक्षा के लिये काफी इन्तजाम करने की बात को राज्य सरकार ने ब्यान में रखा है।

श्री देवगम : क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय में कोई भ्रादेश राज्य सरकार को देगी ?

भी एत० एन० मिश्र : जहां तक योजना कमीशन का ताल्लुक है, योजना कमिशन पिछड़े हिस्सों के लिये और पिछड़े भाइयों की भलाई के लिये काफी जोर देती है भीर योजना कमिशन के यही विचार राज्य बर-कारों को समय समय पर बतलाये जाते हैं।

Tea Industry

*1452. Shri Hem Raj: Will the Minister of Commerce and Industry be plassed to refer to the reply given to Starred Question No. 2628 on the 27th April. 1955 and state:

(a) whether any schemes have since been finalised by Government for the development of Tea Industry in the Kangra District (Punjab); and

(b) if so, whether a copy thereof will be laid on the Table of the House?

The Minister of Commerce (Shri Karmarkar): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Shri Hem Raj: When last time this question was asked the hon. Minister informed me that this matter was under the consideration of the Tea Board. May I know what were the recommendations of the Tea Board?

Shri Karmarkar: In September. 1954 the Government of Punjab approached the Tea Board for financial assistance in this matter. Later on we sent a team of two officers and in the meeting of the executive committee of the Tea Board held on 23rd April, 1955 at Palampur. Kangra District, the Chairman of the Tea Board and members had discussion with local planters. Then it was found that the scheme submitted by the Punjab Government required further consideration and I find that the District Industries' Officer has promised to submit a scheme. Now, all these matters are under consideration.

Shri Bishwa Nath Roy: Is there any scheme under consideration of the Government for tea plantation in any new area in the country?

Shri Karmarkar: In Kangra District or elsewhere I think, otherwise it is a very wide question.